

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 85
सोमवार, 22 जुलाई, 2024/31 आषाढ़, 1946 (शक)

सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार सृजन

85. श्री आनंद भदौरिया:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान आज तक देश में सरकारी और निजी क्षेत्रों में सृजित रोजगार की संख्या का क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही की तुलना में वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही के दौरान क्षेत्र-वार और राज्य-वार रोजगार में कितनी-कितनी वृद्धि/कमी हुई है;
- (ग) क्या सरकार ने वर्ष 2024-25 के दौरान देश के युवाओं को प्रदान करने के लिए कोई लक्ष्य/रोजगार निर्धारित किया है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार युवाओं को पर्याप्त रोजगार प्रदान करने में विफल रही है; और
- (च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा रोजगार सृजन के लिए वर्ष 2024-25 के दौरान क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (च): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान, देश में सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सार्वजनिक और निजी क्षेत्र सहित रोजगार का संकेत देने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) निम्नानुसार है:

(% में)

वर्ष	डब्ल्यूपीआर
2020-21	52.6
2021-22	52.9
2022-23	56.0

स्रोत: पीएलएफएस

उपरोक्त तालिका के आंकड़ें दर्शाते हैं कि देश में पिछले कुछ वर्षों में रोजगार का संकेत देने वाले कामगार जनसंख्या अनुपात में वृद्धि की प्रवृत्ति है।

वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) **अनुबंध** पर है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रकाशित केएलईएमएस (के: पूंजी, एल: श्रम, ई: ऊर्जा, एम: सामग्री और एस: सेवाएं) डेटाबेस सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों सहित अखिल भारतीय स्तर पर रोजगार के रुझान प्रदान करता है। डेटाबेस के नवीनतम आंकड़ों, 2023-24 के अनंतिम अनुमान के अनुसार, देश में रोजगार 2017-18 में 47.5 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 में बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया। 2017-18 से 2023-24 के दौरान रोजगार में कुल वृद्धि लगभग 16.83 करोड़ है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश भर में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय आदि विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं जैसे प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्व-रोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), आदि। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

लोक सभा के दिनांक 22.07.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 85 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की कार्यशील जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	कार्यशील जनसंख्या अनुपात (%)		
	2020-21	2021-22	2022-23
आंध्र प्रदेश	58.6	57.8	58.6
अरुणाचल प्रदेश	48.5	47.1	64.9
असम	50.5	52.1	54.5
बिहार	39.9	39.3	47.0
छत्तीसगढ़	63.6	64.9	70.1
दिल्ली	42.7	42.3	45.8
गोवा	43.4	41.6	45.1
गुजरात	55.0	56.8	61.5
हरियाणा	44.0	42.5	44.9
हिमाचल प्रदेश	69.5	71.2	73.8
झारखंड	59.6	60.7	60.9
कर्नाटक	55.3	53.0	55.6
केरल	46.1	48.8	50.5
मध्य प्रदेश	60.2	60.7	63.4
महाराष्ट्र	53.9	55.9	57.6
मणिपुर	41.0	40.6	48.7
मेघालय	62.0	60.5	65.8
मिजोरम	54.5	48.9	55.2
नागालैंड	49.5	58.4	69.4
ओडिशा	53.5	52.4	58.9
पंजाब	47.2	48.5	50.2
राजस्थान	55.3	54.7	58.8
सिक्किम	71.3	69.9	74.0
तमिलनाडु	56.9	55.8	54.7
तेलंगाना	57.8	58.1	57.7
त्रिपुरा	53.8	50.6	54.3
उत्तराखंड	48.7	48.7	53.5
उत्तर प्रदेश	48.0	50.1	53.9
पश्चिम बंगाल	53.0	52.7	56.1
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	58.2	59.2	60.0
चंडीगढ़	43.1	42.2	45.6
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	54.0	65.8	65.0
जम्मू एवं कश्मीर	55.5	58.3	60.7
लद्दाख	69.1	58.1	57.0
लक्षद्वीप	40.1	37.2	35.5
पुडुचेरी	48.1	51.2	49.6
अखिल भारत	52.6	52.9	56.0

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई